eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

भारत का विदेश व्यापार और राष्ट्रीय उत्पादन की संरचनाः रोजगार और विकास की दृष्टि

[1]पूजा भगत
[1]पूर्व अतिथि शिक्षक राजनीति विज्ञान विभाग, राजधानी कालेज, दिल्ली।

Abstract

भारत का विदेशी व्यापार रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी व्यापार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निर्यातोन्मुख उद्योगों ने कपड़ा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल घटकों जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार घरेलू आदानों और कच्चे माल की मांग में वृद्धि करके रोजगार को प्रोत्साहित करता है, जबकि पूंजीगत वस्तुओं का आयात तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है। हालांकि, रोजगार के प्रभाव क्षेत्रों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं, संरचनात्मक परिवर्तनों से प्रभावित श्रमिकों का समर्थन करने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है। विदेशी व्यापार ने भी उच्च उत्पादन, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान दिया है।

निर्यात वृद्धि ने निर्यात–उन्मुख उद्योगों में उत्पादन को बढ़ावा दिया है, और वैश्विक बाजारों के संपर्क में आने से नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने सहित विदेश व्यापार का समर्थन करने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा और व्यापार संवर्धन उपायों को लागू किया है। हालांकि, विदेशी व्यापार में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जटिल नियमों, बुनियादी ढांचे की बाधाओं, गैर–टैरिफ बाधाओं, विनिमय दर की अस्थिरता और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

विषय संकेतः– भारतीय विदेश व्यापार, राष्ट्रीय उत्पादन की संरचना, रोजगार व विकास की दृष्टि।

Introduction

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, हाल के दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो मुख्य रूप से अपनी विदेशी व्यापार गतिविधियों से प्रेरित है। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, जिसमें निर्यात और आयात दोनों शामिल हैं, देश के रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभावित लाभों का दोहन करने के लिए प्रभावी नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए विदेशी व्यापार, रोजगार और विकास के बीच जटिल संबंधों की व्यापक समझ आवश्यक है।

विदेशी व्यापार भारत में रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निर्यात–उन्मुख उद्योगों के विस्तार ने देश के कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित करने मंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल घटक जैसे उद्योग फले–फूले हैं, जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में ख1,। इसके अलावा, विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों के माध्यम से

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

रोजगार वृद्धि के एक शक्तिशाली अप्रत्यक्ष चालक के रूप में कार्य करता है। बढ़े हुए निर्यात के स्पिलओवर प्रभाव आपूर्ति श्रृंखला में महसूस किए जाते हैं, जिससे कृषि, खनन, परिवहन और अन्य संबंधित क्षेत्रों को लाभ होता है, जिससे रोजगार सृजन मंर वृद्धि होती है। रोजगार के अलावा, विदेशी व्यापार का भारत के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निर्यात का विस्तार वैश्विक बाजार में उच्च उत्पादन, बेहतर उत्पादकता और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देता है। निर्यात के माध्यम से, भारतीय कंपनियां बड़े बाजारों तक पहुंच प्राप्त करती हैं और अपने ग्राहक आधार में विविधता लाती हैं, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और परिचालन क्षमता में वृद्धि होती है। यह, बदले में, तकनीकी प्रगति और नवाचार की सुविधा देता है, क्योंकि कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और समझदार वैश्विक उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। परिणामी उत्पादकता लाभ और तकनीकी स्पिलओवर का समग्र आर्थिक विकास पर गुणक प्रभाव पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक विकास ख्3, को बढ़ावा मिलता है। रोजगार और विकास के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए भारत के विदेशी व्यापार की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। भारत में निर्यात क्षेत्र में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कपड़ा और परिधान, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, ऑटोमोबाइल घटक और रत्न और आभूषण शामिल हैं। आयात पक्ष पर, भारत के विदेशी व्यापार में कच्चा तेल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और सोना जैसी वस्तुएं शामिल हैं। पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात घरेलू उद्योगों और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो आगे चलकर रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है।

भारत के विदेश व्यापार का अवलोकन– भारत का विदेश व्यापार देश के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना निर्यात और आयात की एक विविध श्रेणी की विशेषता है, जो वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देश की स्थिति को दर्शाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी पुस्तिका (2021) के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने निर्यात में लगातार वृद्धि का अनुभव किया है। देश के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में कपड़ा और वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, ऑटोमोबाइल घटक और रत्न और आभूषण शामिल हैं। ये क्षेत्र भारत के निर्यात विकास को चलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

आयात के संदर्भ में, भारत के विदेशी व्यापार में विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं जो घरेलू उद्योगों का समर्थन करती हैं और भारतीय बाजार की मांगों को पूरा करती हैं। महत्वपूर्ण आयातों में कच्चा तेल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और सोना शामिल हैं। पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात घरेलू उद्योगों की वृद्धि और विकास को सक्षम बनाता है, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में योगदान देता है। भारत का विदेशी व्यापार वैश्विक आर्थिक स्थितियों, व्यापार नीतियों, विनिमय दरों और बाजार की मांग सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। विश्व व्यापार संगठन (2021) इस बात पर प्रकाश डालता है कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ अपने व्यापार संबंधों और बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और वार्ताओं में सक्रिय भागीदार रहा है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

इसके अलावा, भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए व्यापार नीतियां बनाती और लागू करती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित विदेश व्यापार नीति, भारत की विदेश व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न उद्योगों के लिए देश मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से एक वैश्विक केंद्र बन गया है। यह परिवर्तन अनुकूल आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण , द्वारा संचालित किया गया है। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता कई क्षेत्रों में निर्यात और आयात की एक विविध श्रेणी है। देश के निर्यात–उन्मुख उद्योगों, जैसे कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसके निर्यात विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बीच, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात घरेलू उद्योगों का समर्थन करता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुगम बनाता है। वैश्विक बाजार के रुझानों की बारीकी से निगरानी करके, प्रभावी व्यापार नीतियों को लागू करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपने विदेशी व्यापार का लाभ उठाना जारी रख सकता है।

विदेश व्यापार के रोजगार निहितार्थ – पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया है और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भारतीय कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित किया है। निर्यात क्षेत्र की वृद्धि का श्रेय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को दिया जाता है। यह मांग उत्पादन को प्रोत्साहित करती है और विनिर्माण, पैकेजिंग, परिवहन और रसद सहित आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार के अवसर पैदा करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी की हैंडबुक (2021) भारत के निर्यात क्षेत्रों की रोजगार–गहन प्रकृति पर प्रकाश डालती है, जो समग्र रोजगार वृद्धि में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू क्षेत्रों से इनपुट और कच्चे माल की मांग को उत्तेजित करके रोजगार पैदा करता है। बढ़े हुए निर्यात के लिए कृषि, खनन और परिवहन सहित विभिन्न उद्योगों से वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करता है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को लाभ होता है और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है

इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात का भारत में रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। ये आयात तकनीकी प्रगति की सुविधा प्रदान करते हैं और घरेलू उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाते हैं। जब भारतीय कंपनियां उन्नत मशीनरी और उपकरण आयात करती हैं, तो उन्हें इन तकनीकों को संचालित करने और बनाए रखने के लिए अक्सर कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इससे उन क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है जो आयातित प्रौद्योगिकियों को अपनाते हैं, समग्र रोजगार वृद्धि में योगदान करते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विदेशी व्यापार के रोजगार निहितार्थ क्षेत्रों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से वे जो तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, श्रम बाजार समायोजन का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी छूटना या रोजगार पैटर्न में बदलाव। इसलिए, एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों से प्रभावित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए नीतियों और रणनीतियों की आवश्यकता है। विदेशी व्यापार भारत में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी का आयात तकनीकी प्रगति का समर्थन करता है और उत्पादकता बढ़ाता है, जिससे इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि होती है। नीति निर्माताओं के लिए विदेशी व्यापार के रोजगार निहितार्थों पर विचार करना और श्रम बाजार समायोजन का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में समावेशी विकास और समर्थन श्रमिकों को सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।

विदेश व्यापार के विकास प्रभाव– विदेशी व्यापार भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है, जो उच्च उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि में योगदान देता है। निर्यात के विस्तार ने नए बाजार खोलकर और भारतीय फर्मों के लिए ग्राहक आधार में विविधता लाकर आर्थिक विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्यात वृद्धि से निर्यातोन्मुखी उद्योगों में उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसा कि भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मांग को पूरा करती हैं, वे अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी पुस्तिका (2021) भारत में निर्यात वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध पर प्रकाश डालती है।

इसके अलावा, विदेशी व्यापार में संलग्न होने से भारतीय फर्मों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता, नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कंपनियां लगातार अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार करने का प्रयास करती हैं, जिससे उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा के संपर्क में आने से फर्मों को कुशल उत्पादन तकनीकों को अपनाने और अपनी प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है।

विदेशी व्यापार भी ज्ञान और विचारों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, तकनीकी स्पिलओवर और नवाचार में योगदान देता है। चूंकि भारतीय कंपनियां वैश्विक भागीदारों और ग्राहकों के साथ बातचीत करती हैं, वे नई तकनीकों, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और बाजार अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए यह जोखिम सीखने और ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देता है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है और उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाग लेने से, भारतीय फर्मों को वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपनी दक्षता, गुणवत्ता और लागत–प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धात्मकता पर यह ध्यान एक गतिशील कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है और निरंतर सुधार

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

को प्रोत्साहित करता है, जिससे न केवल निर्यात करने वाले उद्योगों बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विदेशी व्यापार के विकास प्रभाव सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों में समान नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों को निर्यात–आधारित विकास से अधिक लाभ हो सकता है, जबकि अन्य को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, नीतियों को विविधीकरण को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धी उद्योगों के विकास का समर्थन करने और किसी भी संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए जो विशिष्ट क्षेत्रों में विकास में बाधा डालते हैं।

विदेशी व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण विकास प्रभाव है। निर्यात के विस्तार से उच्च उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। वैश्विक बाजारों के संपर्क के माध्यम से, भारतीय कंपनियां समग्र आर्थिक विकास में योगदान करते हुए उन्नत तकनीकों को अपनाती हैं, और अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करती हैं। हालाँकि, नीतियों को समावेशी विकास सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और उद्योगों के फलने–फूलने के लिए सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

नीतिगत ढांचा और व्यापार संवर्धन उपाय– भारत ने अपनी विदेशी व्यापार गतिविधियों को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा और विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों को लागू किया है। इन नीतियों का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी को आकर्षित करना है निवेश, घरेलू उद्योगों की रक्षा, और सतत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना।

भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से, व्यापार नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करती है जो विदेशी व्यापार को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं। विदेश व्यापार नीति एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है, जो निर्यातोन्मुखी उद्योगों को समर्थन देने के लिए उद्देश्यों, रणनीतियों और प्रोत्साहनों को रेखांकित करती है।

निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और प्रोत्साहन पेश किए हैं। निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना पात्र निर्यातकों को रियायती सीमा शुल्क दरों पर पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति देती है, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करती है और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) योग्य निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, निर्यात उन्मुख उद्योगों के विकास को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा, भारत सक्रिय रूप से विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और समझौतों में लगा हुआ है। इसकी बाजार पहुंच और अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वैश्विक व्यापार नियमों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और डब्ल्यूटीओ चर्चाओं में भारत की भागीदारी देश को अपने हितों की वकालत करने और अपने उद्योगों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के उपायों को भी लागू किया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम। एफडीआई उत्पादकता, प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थानांतरण, और भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन। विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकृत एफडीआई नीतियों की शुरूआत विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों ने विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करें। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा उपायों और प्रतिकारी शुल्क जैसे व्यापार उपायों को लागू किया है। इन उपायों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं को संबोधित करना, घरेलू उत्पादकों को आयात में वृद्धि से बचाना और घरेलू उद्योगों के लिए एक समान अवसर बनाना है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने निर्यातकों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए विशेष संस्थानों और निर्यात प्रोत्साहन परिषदों की स्थापना की है। एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (थ्म्ब्) जैसी संस्थाएं निर्यातकों को वित्तीय और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी में मदद मिलती है।

भारत ने एक व्यापक नीति ढांचा विकसित किया है और अपनी विदेशी व्यापार गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों को लागू किया है। निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी निवेश को आकर्षित करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में शामिल होने पर सरकार के ध्यान ने भारत के विदेशी व्यापार के विकास में योगदान दिया है। प्रोत्साहन का प्रावधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा भारत की व्यापार नीति के ढांचे के प्रमुख तत्व हैं।

5 **चुनौतियां और बाधाएं–** जबकि भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि और लाभ हुआ है, यह विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करता है जिन्हें निरंतर विकास के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। ये चुनौतियाँ भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकती हैं, निर्यात वृद्धि में बाधा डाल सकती हैं और विदेशी व्यापार क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।

प्राथमिक चुनौतियों में से एक जटिल विनियामक वातावरण और व्यापार में शामिल नौकरशाही प्रक्रियाएं हैं। बोझिल दस्तावेजीकरण, लंबी निकासी प्रक्रियाएँ, और प्रशासनिक बाधाएँ लेन–देन की लागत बढ़ा सकती हैं और विदेशी व्यापार संचालन में अक्षमताएँ पैदा कर सकती हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कागजी कार्रवाई को कम करने और कुशल सीमा शुल्क निकासी तंत्र को लागू करने से इन चुनौतियों को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाएं भारत के विदेशी व्यापार के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे सहित अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना के कारण देरी हो सकती है, उच्च रसद लागत और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। कनेक्टिविटी में सुधार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बढ़ाने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, इन बाधाओं को दूर करने और माल की निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है।

गैर–टैरिफ बाधाएं (एनटीबी) भी भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। ये बाधाएँ, जैसे तकनीकी नियम, उत्पाद मानक, और स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, विदेशी बाजारों तक पहुँचने में बाधाएँ पैदा कर सकते हैं। मानकों को सुसंगत बनाने, अनुपालन ढांचे को मजबूत करने और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को बढ़ाने से एनटीबीएस को संबोधित करने और भारतीय उत्पादों के लिए

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

बाजार पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है। विनिमय दर की अस्थिरता एक और बाधा है जो भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करती है। विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है और व्यापारियों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विनिमय दर जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए तंत्र विकसित करना, मुद्रा बाजारों में स्थिरता को बढ़ावा देना और हेजिंग विकल्प प्रदान करना विदेशी व्यापार पर विनिमय दर की अस्थिरता के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताएं और भू–राजनीतिक तनाव भारत के विदेशी व्यापार के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। वैश्विक व्यापार गतिशीलता में बदलाव, प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की व्यापार नीतियों में बदलाव और व्यापार विवाद निर्यात संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीय व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं ख्30,। निर्यात स्थलों में विविधता लाने, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल होने से वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है।

सेक्टर–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कुछ श्रम प्रधान क्षेत्र, जैसे कपड़ा, कम श्रम लागत वाले देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। उत्पादकता बढ़ाने, कौशल विकास में निवेश करने और उन्नत विनिर्माण तकनीकों को अपनाने से इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

भारत के विदेश व्यापार को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें निरंतर वृद्धि और विकास के लिए दूर करने की आवश्यकता है। विनियामक जटिलताओं को संबोधित करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, गैर–टैरिफ बाधाओं से निपटना, विनिमय दर की अस्थिरता का प्रबंधन करना, वैश्विक अनिश्चितताओं को दूर करना और क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करना भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष – भारत का विदेशी व्यापार रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरा है। निर्यात–उन्मुख उद्योगों के विस्तार से रोजगार सृजन हुआ है, विशेषकर कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल घटकों जैसे क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार अप्रत्यक्ष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को लाभान्वित करते हुए, घरेलू क्षेत्रों से इनपुट और कच्चे माल की मांग को उत्तेजित करके रोजगार उत्पन्न करता है। घरेलू उद्योगों में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देकर पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात ने भी रोजगार वृद्धि में योगदान दिया है।

विदेशी व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक विकास प्रभाव पड़ा है, जिससे उच्च उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजारों के संपर्क ने नवाचार, तकनीकी प्रगति और कुशल उत्पादन तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में शामिल होने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने से भारत के विदेशी व्यापार के विकास को और समर्थन मिला है। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार का समर्थन करने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा और व्यापार संवर्धन उपायों को लागू किया है। इनमें निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में संलग्नता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के

उपाय शामिल हैं। हालांकि, क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने, व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने और विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। भारत के विदेशी व्यापार ने महत्वपूर्ण रोजगार और विकास के प्रभाव का प्रदर्शन किया है।

संदर्भ–

[1]. Carmona, S., Farazmand, H., &Sosvilla-Rivero, S. (2020). Sustainable investment: A bibliometric analysis. Journal of Cleaner Production, 244, 118853.
[2]. Rennings, K., Wiggering, H., & Hoffmann, E. (2018). Sustainable investment: Concepts, methodologies, and challenges. Journal of Cleaner Production, 181, 1-5.
[3]. Draz, M. U., & Ahmad, F.. (2018, January 1). Financial Crises and Key Economic Sectors of China and India: A Comparative Review of 1991-2010. SHS Web of Conferences, 56, 04002. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185604002
[4]. UNCTAD. (2020). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations Conference on Trade and Development.
[5]. World Bank. (2020). India. Retrieved from https://data.worldbank.org/country/india
[6]. Global Reporting Initiative (GRI). (n.d.). About GRI. Retrieved from https://www.globalreporting.org/about-gri/
[7]. Lacalle, D.. (2020, February 14). The Importance of Profit and Sound Financing in Socially Responsible Investment. Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, 2(2), 1. https://doi.org/10.35995/jbafp2020011
[8]. [Principles for Responsible Investment (PRI). (n.d.). About PRI. Retrieved from https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
[9]. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). (n.d.). About the TCFD. Retrieved from https://www.fsb-tcfd.org/about/
[10]. García-Gómez, F. J., Prieto, V. F. R., Sánchez-Lite, A., Fuentes-Bargues, J. L., & González, C. C.. (2021, June 8). An Approach to Sustainability Risk Assessment in Industrial Assets. Sustainability, 13(12), 6538. https://doi.org/10.3390/su13126538

[11]. Government of India. (2019). National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business. Retrieved from https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesActNotification_07nov2019.pdf
[12]. Ministry of Housing and Urban Affairs. (2020). Smart Cities Mission. Retrieved from https://smartcities.gov.in/
[13]. NITI Aayog. (2020). SDG India Index & Dashboard 2019-20. Retrieved from https://niti.gov.in/sdg-india-index-dashboard-2019-20
[14]. Soni, K. K.. (2018, November 21). Is Malnutrition Still a Serious Problem in India? A Comprehensive Review. Journal of Medical Science and Clinical Research, 6(11). https://doi.org/10.18535/jmscr/v6i11.96
[15]. Kocmanová, A., Dočekalová, M., Meluzín, T., &Škapa, S.. (2020, October 10). Sustainable Investing Model for Decision Makers (Based On Research of Manufacturing Industry in the Czech Republic). Sustainability, 12(20), 8342. https://doi.org/10.3390/su12208342

[16]. UNCTAD. (2020). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations Conference on Trade and Development.
[17]. Kato, T., &Hiroi, Y.. (2021, November 4). Wealth disparities and economic flow: Assessment using an asset exchange model with the surplus stock of the wealthy. Plos One, 16(11), e0259323. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259323
[18]. Taliento, M., Favino, C., &Netti, A.. (2019, March 22). Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate 'Sustainability Advantage' from Europe. Sustainability, 11(6), 1738. https://doi.org/10.3390/su11061738
[19]. Ito, H.. (2022, August 31). On the Correlation between Market Risk Premiums and SDGs. Communications of the Japan Association of Real Options and Strategy, 12(1), 35-50. https://doi.org/10.12949/cjaros.12.1_35
[20]. Przychodzen, J., Pascual, F. G., Przychodzen, W., &Larreina, M.. (2016, October 24). ESG Issues among Fund Managers—Factors and Motives. Sustainability, 8(10), 1078. https://doi.org/10.3390/su8101078
[21]. Government of India. (2019). National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business. Retrieved from https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesActNotification_07nov2019.pdf
[22]. NITI Aayog. (2020). SDG India Index & Dashboard 2019-20. Retrieved from https://niti.gov.in/sdg-india-index-dashboard-2019-20
[23]. Sgammini, R.. (2023, January 14). A Comparative Risk-adjusted Performance Evaluation of South African SRI Funds and the FTSE/JSE over the Covid-19 Period. International Journal of Economics and Financial Issues, 13(1), 46-55. https://doi.org/10.32479/ijefi.13717
[24]. Kocmanová, A., Dočekalová, M., Meluzín, T., &Škapa, S.. (2020, October 10). Sustainable Investing Model for Decision Makers (Based On Research of Manufacturing Industry in the Czech Republic). Sustainability, 12(20), 8342. https://doi.org/10.3390/su12208342
[25]. Zhao, H., Zhang, J., & Ge, Y.. (2021, July 9). Operation mode selection of NIMBY facility Public Private Partnership projects. Plos One, 16(7), e0254046. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254046
[26]. UNEP FI. (2019). Principles for Responsible Banking. Retrieved from https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
[27]. World Economic Forum. (2020). The Future of Sustainable Investment. Retrieved from https://www.weforum.org/whitepapers
[28]. An, H., Yan, W., Bian, S., & Ma, S.. (2019, October 1). Rain Monitoring with Polarimetric GNSS Signals: Ground-Based Experimental Research. Remote Sensing, 11(19), 2293. https://doi.org/10.3390/rs11192293
[29]. Fan, L., Wang, Y., Fang, X., & Jiang, J.. (2022, October 1). To Predict the Power Generation based on Machine Learning Method. Journal of Physics Conference Series, 2310(1), 012084. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2310/1/012084
[30]. Zhang, Zhendong et al. (2021, January 1). Solar Radiation Intensity Probabilistic Forecasting Based on K-Means Time Series Clustering and Gaussian Process Regression. Ieee Access, 9, 89079-89092. https://doi.org/10.1109/access.2021.3077475